गढ़कुंडार प्रोजेक्टः बुंदेलखंड में जल संग्रह का सफल मॉडल

- *महज दो प्रतिशत रह गई परियोजना क्षेत्र में सूखे कुओं की संख्या*
- *पूरे बुंदेलखंड में अपनाई जा सकती है विकसित तकनीक*

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र, झांसी की गढ़कुंडार–डाबर जलसमेट परियोजना के नतीजे लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे इस क्षेत्र के लिए राहत लेकर आए हैं। इस दौरान मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के इस परियोजना क्षेत्र के 53.3 प्रतिशत कुओं में जहां दो मीटर से ज्यादा जल स्तर बढ़ गया, वहीं सूखे कुओं की संख्या भी घटकर दो प्रतिशत रह गई। अब इन कुओं के पानी का उपयोग न सिर्फ पेयजल बल्कि रबी की फसल के लिए सिंचाई में भी किया जा रहा है। चूंकि इस क्षेत्र की जलवायु और सामाजिक–आर्थिक दशाएं बुंदेलखंड क्षेत्र का सटीक प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसे में यहां विकसित तकनीक को पूरे बुंदेलखंड विशेषकर लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनाकर सूखे की समस्या से निजात पाई जा सकती है।

बताते चलें कि वर्ष 2005 तक इस क्षेत्र में सूखे का मंजर दिल दुखाने वाला था। 86 प्रतिशत कुएं सूखने से न सिर्फ मवेशी बल्कि लोगों के लिए भी पेयजल आसानी से उपलब्ध न था। फसल प्रभावित हो रही थी सो अलग। गरीबी, बेरोजगारी के कारण यहां से लोगों के पलायन करने की भी समस्या बनी हुई थी। ऐसे में राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केंद्र, झांसी के वैज्ञानिकों ने गढ़कुंडार–डाबर जलसमेट परियोजना के तहत क्षेत्र के पुनरूद्धार का बीड़ा उठाया। शुरूआत मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील के पिछड़े क्षेत्र गढ़कुंडार–डाबर से हुई। परियोजना में तीन ग्राम पंचायतों के छह मजरों (कुंडार, रौतियाना, डाबर, शिवरामपुर, स्यामसी एवं उबौरा) की 850 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया।

इस दौरान सात बड़े चैक डैम तथा दो कम लागत वाले चैक डेम बनाने के साथ ही नाले के किनारे स्थित करीब 40 हेक्टेयर जमीन की मेड़ बंदी की गई। तीन जल विस्तारकों की मदद लेकर जल भंडारण किया गया। इसके अलावा जल समेट में कृषि एवं कृषिवानिकी विकास के लिए उन्नत प्रजातियों, तकनीकों एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग के प्रदर्शन किए गए। क्षेत्र में जहां एक ओर आंवला, नीबू तथा बेर जैसे फलदार पेड़ लगाए तो वहीं दूसरी ओर मूंगफली, सोयाबीन तथा गेहूं की शुद्ध फसलों को भी बतौर प्रोत्साहन लगाया गया। आजीविका सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को लाखकीट पालन, गोंद एवं राल देने वाले वृक्षों की खेती, बकरी पालन तथा चेक डैम में मछली पालन जैसी गतिविधियां शुरू की गईं।

प्रोजेक्ट शुरू होने के तीन साल बाद ही क्षेत्र की कायापलट होनी शुरू हो गई। ताजे आंकड़ों के अनुसार उपचारित तथा गैर–उपचारित क्षेत्र में जल अपवाह तथा मृदाहानि में जहां 34 से 43 प्रतिशत कमी हुई,

वहीं जलसमेट क्षेत्र के 53.3 प्रतिशत कुओं में दो मीटर से ज्यादा जलस्तर की वृद्धि पाई गई। उपचारित जल समेट क्षेत्र के नालों में सतही पानी वर्ष भर पाया गया जबकि, गैर–उपचारित क्षेत्र में सतही जल केवल चार महीने मिलता है। उपचारित क्षेत्र में फसल सघनता 116 प्रतिशत तक होने से फसल उत्पादन में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा परियोजना क्षेत्र में फलदार वृक्षों की बहुतायत होने लगी है। साथ ही चैक डैम आदि के निर्माण संबंधी कार्यों से स्थानीय युवकों को रोजगार मिला। वहीं स्वयं सहायता समूहों आदि के गठन ने किसानों को आत्मनिर्भर होने में मदद की।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र के निदेशक डॉ एसके ध्यानी परियोजना की सफलता का श्रेय किसानों को देना नहीं भूलते। वह बताते हैं कि वर्ष 2004 से 2007 तक भयंकर सूखा झेल चुके इस क्षेत्र में अब हालात खुशनुमा होने की ओर हैं। इस साल 43 फीसदी कम बारिश होने के बावजूद चैक डेम और कुओं में पर्याप्त पानी है। यह सब परियोजना के चलते संभव हो सका है। अति पिछड़े जिलों में शुमार टीकमगढ़ में जल संकट को दूर करने में इससे काफी सहायता मिली। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। डॉ ध्यानी के अनुसार गढ़कुंडार–डाबर परियोजना की सफलता को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स यानी इक्रीसेट ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र को झांसी में एक अन्य वाटर शेड प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा है। यह देश में बनने वाले नौ मॉडल वाटर शेड्स में से एक होगा।

साभार– मास मीडिया प्रोजेक्ट, दीपा